मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पूनिया व गुर्जर ने राज्यसभा का नामांकन भरा

सतीश पूनिया व अल्का गुर्जर के अनुभव का लाभ अब प्रदेश और देश को मिलेगा- भजनलाल

जयपुर, 8 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉ. सतीश पूनिया एवं डॉ. अल्का गुर्जर के अनुभव का फायदा अब प्रदेश के साथ देश को भी मिलेगा। दोनों का संसद के उच्च सदन में जाना राजस्थान के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा की "हां" पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास रथ और ग्राम विकास चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान द्वारा आमजन की भागीदारी के साथ जल संरक्षण को जल आंदोलन का रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में किए गए ऐतिहासिक कार्यों का जन-जन तक प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। इसी को लेकर 5 जून से 21 जून तक "12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" कार्यक्रम के जरिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं।

■ भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 साल के ऐतिहासिक कार्यों के प्रचार के लिए 5 से 21 जून तक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक ली। बैठक के बाद राज्यसभा प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अल्का गुर्जर ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नामांकन भरा।

विधायक दल की बैठक के बाद राज्यसभा प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अल्का गुर्जर ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पेश किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित अन्य विधायकगण मौजूद थे।

तृणमूल कांग्रेस नेता जहाँगीर खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया

कोलकाता, 08 जून। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता लाया जा रहा है।

सूत्रों का दावा है कि जहांगीर खान नेपाल सीमा के रास्ते देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर विशेष कार्य बल की टीम ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से फरार घोषित माना जा रहा था।

■ वह नेपाल सीमा के रास्ते देश से भागने की फिराक में पकड़ा गया।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में जहांगीर खान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में उन्हें पहले अदालत से अंतरिम सुरक्षा मिली थी। इसके अलावा, फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्निर्वाचन से पहले भी उन्हें उच्च न्यायालय से सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ था। हालांकि, 26 मई को उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ जारी सभी सुरक्षा आदेश वापस ले लिए, जिसके बाद पुलिस के लिए गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया।

एसआई पेपर लीक में सहायक लेखाधिकारी नागेश यादव गिरफ्तार

घटना सामने आने के बाद से वह अजीतगढ़ में अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होकर फरार हो गया था

जयपुर, 8 जून। बहुचर्चित उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए के इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे सहायक लेखाधिकारी नागेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नागेश कुमार यादव (32) निवासी हरदास का बास, ढाणी पड़ाव की, तहसील श्रीमाधोपुर, थाना अजीतगढ़, जिला सीकर है। वह उस समय पंचायत समिति अजीतगढ़, जिला सीकर में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यरत था। घटना सामने आने के बाद वह ड्यूटी से अनुपस्थित होकर फरार हो गया था। एसओजी ने सीकर पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया है।

■ एसओजी की जाँच में खुलासा हुआ कि नागेश ने अपने भाई सुरजीत सिंह यादव को उपनिरीक्षण भर्ती परीक्षा में चयनित कराने के लिए पुरुषोत्तम दाधीच से 7.50 लाख रूपए में प्रश्न पत्र खरीदा था।

जांच में सामने आया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के प्रश्न पत्रों के उत्तर तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) सदस्य बाबूलाल कटारा से कुन्दन कुमार पंड्या ने प्राप्त किए थे। इसके बाद कुन्दन कुमार पंड्या ने प्रश्नों के उत्तर अपने परिचित संदीप कुमार लाटा और पुरुषोत्तम दाधीच को उपलब्ध कराए। उस समय पुरुषोत्तम दाधीच स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यरत था।

एसओजी जांच में खुलासा हुआ कि पुरुषोत्तम दाधीच और नागेश कुमार यादव एक ही विभाग में काम करते थे। नागेश ने अपने भाई सुरजीत सिंह यादव को उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित कराने के उद्देश्य से पुरुषोत्तम दाधीच से 7.50 लाख रुपए में पेपर खरीदा था।

लीक पेपर का अध्ययन कर परीक्षा देने के कारण सुरजीत यादव ने हिन्दी विषय में 200 में से 190.79 अंक तथा सामान्य ज्ञान में 200 में से 158.27 अंक प्राप्त किए। उत्कृष्ट अंकों के आधार पर वह मेरिट सूची में 18वें स्थान पर रहा और उपनिरीक्षक पद पर अंतिम रूप से चयनित हो गया।

एसओजी ने इस मामले में सुरजीत सिंह यादव को 9 अक्टूबर 2024 को तथा पुरुषोत्तम दाधीच को 2 जून 2025 को गिरफ्तार किया था। दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

एडीजी बंसल ने बताया कि नागेश कुमार यादव लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे तथा उस पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। आखिरकार तकनीकी निगरानी और सीकर पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

'दिल्ली जिमखाना, पोलो ग्राउण्ड जैसे हरित क्षेत्रों का अधिग्रहण क्यों करना चाहते हैं?'

हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा, "दिल्ली में छोटा सा फेफड़ा है, आप उसे भी लेना चाहते हैं तो ले लें"

नई दिल्ली, 08 जून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के दिल्ली जिमखाना, पोलो ग्राउंड जैसे हरित क्षेत्र को अधिग्रहीत करने के केन्द्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली में काफी कम हरित क्षेत्र है। उसे हटाने के बाद प्रदूषण से दम घुटकर हमारी मौत हो जाएगी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने ये टिप्पणी इंडियन पोलो एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि आपको पोलो ग्राउंड क्यों चाहिए। आप दिल्ली जिमखाना समेत सभी हेरिटेज ढ ांचों का क्या करेंगे। आप उनका क्या करने वाले हैं। आप वहां बीस मंजिला बिल्डिंग खड़ी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके में थोड़ी बहुत सांसे बची हुई हैं। हम सभी घुटकर मरने वाले हैं। सरकार को 200 सालों में इनकी कोई जरुरत नहीं हुई। दिल्ली में एक छोटा सा फेफड़ा है, आप उसे भी चाहते हैं कि ले लें।

■ दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप सभी हेरिटेज ढांचों का क्या करेंगे,आप वहाँ बीस मंजिला बिल्डिंग खड़ी करेंगे?

दरअसल, इंडियन पोलो एसोसिएशन ने याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है। पोलो एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर कर केन्द्र सरकार के, ग्राउन्ड को खाली करने के आदेश को चुनौती दी है, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने नोटिस पर रोक संबंधी अर्जी पर कोई विचार नहीं किया और एक सामान्य नोटिस जारी कर दिया। इसपर उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट को निर्देश दिया कि वो खाली करने के नोटिस पर रोक की अर्जी पर फैसला करे।

सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित ने केन्द्र सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार केवल रक्षा जरुरतों के लिए इन इलाकों का अधिग्रहण करना चाहती है। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या ऊंची बिल्डिंग बनना जनता के हित में है। दिल्ली में केवल ऊंची बिल्डिंग हैं। इसे भगवान ही बचा सकते हैं।

अब उज्ज्वला योजना के तहत सिर्फ 4 सिलैंडर मिलेंगे

नई दिल्ली, 08 जून। केंद्र सरकार ने प्रमुख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडरों कीसंख्या साल के 12 से घटाकर चार कर दी है। यह निर्णय औसत घरेलू खपत के स्तर को देखते हुएलिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण माल खनूजा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। शुरुआत में लाभार्थियों को प्रति वर्ष सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडर मिलते थे। पिछले साल सब्सिडी कोटा घटाकर नौ कर दिया गया था, और अब इसे और कम करके चार कर दिया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सैन्य व सुरक्षाकर्मियों को रक्षा अलंकरण प्रदान किए

उन्होंने सात कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र तथा 29 शौर्य चक्र प्रदान किए

नई दिल्ली, 08 जून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण-2026 समारोह के प्रथम चरण के दौरान, रक्षा बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश पुलिसकर्मियों को सात कीर्ति चक्र (दो मरणोपरांत), 15 वीर चक्र (तीन मरणोपरांत) और 29 शौर्य चक्र (एक मरणोपरांत) प्रदान किए।

वीरता पुरस्कार, कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैन्य एवं सुरक्षाकर्मियों को प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति ने आज जिन्हें सम्मानित किया, उनके नाम इस प्रकार हैं- कीर्ति चक्र (मरणोपरांत): सिपाही जंजाल प्रवीन प्रभाकर तथा लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी।

■ राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण-2026 समारोह में कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैन्य एवं सुरक्षाकर्मियों को सम्मानित किया गया।

कीर्ति चक्र: लांस नायक मीनात्ची सुंदरम ए, नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह, एयर कमोडोर प्रसांत बालकृष्णन नायर तथा कैप्टन लालरिनावमा सैलो।

वीर चक्र (मरणोपरांत): सब इंस्पेक्टर (जीडी) मोहम्मद इम्तेयाज, कांस्टेबल (जीडी) दीपक चिंगाखम तथा राइफलमैन सुनील कुमार।

वीर चक्र: कर्नल कोषांक लांबा, ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा, विंग कमांडर (वर्तमान में ग्रुप कैप्टन) जॉय चंद्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, स्क्वाड्रन लीडर (वर्तमान में विंग कमांडर) सार्थक कुमार, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट (वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर) आरशवीर सिंह ठाकुर तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार।

टीएमसी के 20 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्तमान स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस के केवल कुछ ही नेताओं की विश्वसनीयता बची हुई है। अब बंगाल की जनता उनके साथ किसी भी तरह के जुड़ाव को बहुत बुरी नज़र से देखेगी।

बंगाल के लोगों, विशेष रूप से डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए एक और बड़ी जीत यह रही कि तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगी जहाँगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस घटनाक्रम के साथ ही , राज्यसभा सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से तथा अपने राज्यसभा पद से भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले सुखेन्दु रॉय ने तृणमूल कांग्रेस के कामकाज की खुलकर आलोचना की थी।

उन्होंने पार्टी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर भी तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि पार्टी के कई पदाधिकारियों से जुड़े नए-नए घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। इन नेताओं पर अवैध रूप से धन कमाने के अलावा, सैक्स रैकेट चलाने और महिलाओं को धमकाने जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं।

सुखेन्दु शेखर रॉय इससे पहले भी पार्टी से दूरी बना चुके थे, जब राज्य के एक सरकारी अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि पार्टी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट किया गया।

विरोध की इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी और उसके सभी मामलों से लगभग अलग कर दिया था। लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी छोड़ने का अंतिम फैसला उन्होंने तब लिया, जब प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से उनके पिता की स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका की खुलकर तारीफ की।

प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में सुखेन्दु शेखर रॉय के पिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इंडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संयुक्त कार्रवाई की एक छोटी शुरुआत हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सभी पार्टियों की बैठक बुलाने के लिए आग्रह किया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और कृषि मुद्दों पर चर्चा हो। बैठक के बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब ब्लॉक हर दो महीने में बैठक करेगा तथा अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। इसके अलावा, यह तय किया गया कि सदस्य पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता आगामी मानसून सत्र के दौरान दैनिक समन्वय बैठकें करेंगे।

हाई कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ियों पर सीबीएसई को नोटिस जारी किया

एनएसयूआई के अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 12 जून को तय

नई दिल्ली, 08 जून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में हुई गड़बड़ियों और ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) से जुड़ी शिकायतों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को करने का आदेश दिया।

यह याचिका नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की ओर से इसके अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दायर की है। सुनवाई के दौरान, सीबीएसई के वकील एमए नियाजी ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल के छात्र संगठन ने दायर किया है। शिक्षा का इस तरह राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस पर एनएसयूआई के वकील ने कहा कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इस बात की वजह नहीं हो सकती कि वे याचिका दायर करने के योग्य नहीं हैं।

■ याचिका में नोटिफिकेशन के लिए नया विंडो, विवादित आंसर शीट की दोबारा फिजिकल जाँच तथा सभी गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच की मांग की गई।

सीबीएसई ने कहा कि पोर्टल एक महीने के लिए नहीं खोला जा सकता। सीबीएसई छात्रों की समस्याओं पर विचार कर रही है।

याचिका में कहा गया है कि जिन छात्रों के कम अंक आए हैं या स्पष्ट नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त नंबर दिए जाएं। याचिका में मांग की गई है कि वेरिफिकेशन के लिए नई विंडो, विवादित आंसर शीट की दोबारा फिजिकल जांच और 12वीं के रिजल्ट पर असर डालने वाली कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। याचिका में भविष्य के लिए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए सही सुरक्षा उपाय, प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश बनाने और लागू करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई हैं, ताकि ऐसी शिकायतें दोबारा न हो।

जुलाई में दस्तखत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हस्ताक्षर हो सकते हैं। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि हालिया टैरिफ विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़े शेष मुद्दों को सुलझाने में लगे हुए हैं। इस समझौते से बाजार तक पहुंच (मार्केट एक्सेस) बेहतर होने और भारतीय निर्यातकों को कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलने की उम्मीद है। गोयल के बयान से यह भी संकेत मिलता है कि पिछले कुछ सप्ताहों में वार्ताओं ने गति पकड़ी है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि दोनों पक्ष पहले की अपेक्षा जल्द किसी महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा कर सकते हैं।

फिलिपींस में 7.8 तीव्रता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वोल्केनोलॉजी एंड सैस्मोलॉजी ने बताया कि मुख्य झटके के बाद एक घंटे से ज़्यादा समय तक झटके महसूस किए गए। दक्षिणी मिंडानाओ में 7.22 लाख की आबादी वाले शहर जनरल सैंटोस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में एक तीन मंज़िला इमारत, मलबे और धूल के गुबार के साथ ढ हती दिख रही है।

स्थानीय पुलिस प्रवक्ता रॉबर्ट डगुन ने बताया कि शहर के सेंट एलिज़ाबेथ अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ऑफिस ऑफ़ सिविल डिफेंस डिप्टी प्रवक्ता डिएगो ऑगस्टिन मारियानो के अनुसार अब तक 19 मौतों की सूचना मिली है, जिनमें 16 मौतें सोक्ससारजेन क्षेत्र और तीन मौतें दावाओ क्षेत्रसे दर्ज की गई हैं। हालांकि, इन आंकड़ों की अभी आधिकारिक पुष्टि की जा रही है।

पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थे। इन चार टेंडरों को लेकर ठेका फर्म को एक रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ था। इसके अलावा, इरकॉन से मेल आने के बाद स्वयं विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा। इसलिए उसे जमानत दी जाए। इसका विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने विरोध किया व कहा कि ठेका फर्म के खिलाफ शिकायतों को जानबूझकर अनदेखा किया गया और प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए।

अमेरिका-इज़रायल को कुछ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सबसे बड़ा नुकसान मध्यपूर्व को ही हुआ है। ईरान, लेबनान, इज़रायल और पड़ोसी खाड़ी राज्यों में हजारों लोग मारे गए हैं। नागरिकों के विस्थापन में तेज़ वृद्धि हुई है, और पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इसका शिकार बनी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से आपूर्ति में संभावित व्यवधान के डर से तेल की कीमतें बार-बार बढ़ी हैं, क्योंकि विश्व का लगभग पांचवां हिस्सा तेल व्यापार इसी मार्ग से होता है। ऊर्जा लागत कई देशों में बढ़ी है, जिससे विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कीमत चुकाई है। अमेरिकी सैनिक तनावपूर्ण माहौल में तैनात हैं, हताहतों की संख्या बढ़ी है, और युद्ध के लिए सार्वजनिक समर्थन सीमित दिख रहा है। सैन्य संसाधनों और हथियारों पर दबाव बढ़ा है, जिससे लंबे समय तक इसे जारी रखने को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

भारत के लिए यह संघर्ष कोई दूर की भू-राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष आर्थिक और रणनीतिक चिंता का विषय है।

सबसे पहले, ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। भारत अपनी कच्ची तेल आवश्यकताओं का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी से आता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में किसी भी तरह की रूकावट से तुरंत आयात की लागत बढ़ जाती है और देश में महंगाई का दबाव बनता है। बढ़ती तेल कीमतें भारत के चालू खाता घाटे (करैंट अकाउन्ट डैफिसिट) को बढ़ा सकती हैं और रुपये पर दबाव डाल सकती हैं।

दूसरा, भारत के लाखों प्रवासी श्रमिक खाड़ी क्षेत्र में हैं। संघर्ष की तीव्रता उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और उस रैमिटैंस (विदेशों से भेजी जाने वाली कमाई) को प्रभावित कर सकती है, जो हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान देता है।

तीसरा, यह युद्ध भारत के कूटनीतिक संतुलन की जटिलता बढ़ाता है। नई दिल्ली के संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल के साथ नज़दीकी रणनीतिक संबंध हैं, साथ ही ईरान के साथ भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध बने हुए हैं, विशेषकर चाबहार बंदरगाह जैसी कनैक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर। लंबा संघर्ष भारत के लिए फैसले लेने की गुंजाइश को कम करता है।

अंत में, पश्चिम एशिया में निरंतर अस्थिरता से वैश्विक विकास धीमा हो सकता है, भारतीय निर्यात को नुकसान पहुँचा सकता है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है।

ऋतबृत की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

कोलकाता, 8 जून। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर चल रहा विवाद अब कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और बालीगंज से विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता का दर्जा दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

सोमवार को उनके अधिवक्ता शिशिरन्या बनर्जी ने न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने किसी राजनीतिक दल के पर्याप्त समर्थन के बिना विपक्ष के नेता की नियुक्ति का निर्णय लिया है, जो प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

■ बंगाल में नेता प्रतिपक्ष ऋतबृत को नियुक्त करने के खिलाफ टीएमसी नेता शोभनदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख निर्धारित की है। साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे मामले, से संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी करें।

नीट पेपर बनाने वालों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये प्रतिबंध 21 जून को परीक्षा आयोजित होने तक लागू रहेंगे। एनटीए ने किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए कई परतों वाली आंतरिक सुरक्षा भी लागू की है।

री-एग्ज़ाम को लीक-प्रूफ बनाने के लिए, अधिकारियों ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। भारतीय वायु सेना को प्रश्नपत्रों के परिवहन का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा, परीक्षा से संबंधित कार्यों के लिए लगभग पांच लाख सुरक्षा कर्मियों को पूरे देश में तैनात किए जाने की संभावना है।

अधिकारियों ने एआई-सक्षम निगरानी कैमरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बढ़ी हुई निगरानी का भी ऐलान किया है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह के उल्लंघन के प्रयास को रोका जा सके।

नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए विस्तृत प्रश्नपत्र निर्माण प्रोटोकॉल हुआ करता है। प्रश्नपत्रों के कई सैट तैयार किए जाते हैं, और प्रत्येक सेट के लिए अलग टीमों को जिम्मेदारी दी जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति यह न जान पाए कि अंततः कौन सा प्रश्न पत्र परीक्षा में चुना जाएगा।

लेकिन इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, हाल ही में हुए लीक ने प्रक्रिया की कमजोरियों को उजागर किया। सीबीआई की जांच के दौरान, पीवी कुलकर्णी का नाम इस प्रकरण में सामने आया, जिन्होंने कथित तौर पर कई वर्षों तक एनटीए में विषय विशेषज्ञ के रूप में काम किया था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें नीट प्रश्नपत्र के कई सैटों तक पहुँच प्राप्त थी। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है।

शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के बीच कई दौर की चर्चाओं के बाद, अधिकारियों ने घोषणा की कि री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। पेपर लीक की जांच भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई है।

विशाखापत्तनम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, घायलों और फंसे श्रमिकों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने तथा घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908